www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 338 || लखनऊ
रविवार
15 मार्च 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
दैनिक
तमसा संकेत
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

मौसम
सूर्योदयः 06:14
सूर्यास्तः 06:15
अधिकतमः 33°00
न्यूनतमः 19°00

» पेज 03

विशेष समाचार

भारत में बेहतर शासन प्रणाली के ... » पेज 02
गैस के लिए गाड़ी के रास्ते पर लेटा... »पेज 04
61 के हुए आमिर खान...

सरकार बोली-दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली-NCR की इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी संस्थाओं को एक महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने पेलेट्स, खासकर रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) पेलेट्स के अस्थायी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने यह आदेश जारी किया है। रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल (RDF) असल में कचरे से बनाया गया एक तरह का ईंधन है। इसमें नगर निगम और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सूखे कचरे- जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़ा और लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है।

पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी में 5-30% कटौती

ईंधन संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार ने खर्च कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30% तक कटौती को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने कहा कि बचाए गए पैसे का इस्तेमाल आम लोगों को राहत देने के लिए किया जाएगा।अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक डीजल की औसत कीमत भी बढ़कर 4.85 डॉलर प्रति गैलन हो गई है, जो युद्ध से पहले लगभग 3.71 डॉलर थी। इससे शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ने और सामान महंगा होने की आशंका है।

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा है कि अगर इस्लामिक गणराज्य की सरकार गिरती है तो वे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में अमेरिका में रह रहे पहलवी ने कहा कि वह पहले से ही एक ट्रांज़िशनल सिस्टम यानी तैयार करने पर काम कर रहे हैं।

एआई वकील के दिमाग की जगह नहीं ले सकता
सुप्रीम कोर्ट के जज बोले-एआई समय बचाने में मददगार

तमसा संकेत, एजेंसी

हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा कि AI वकील के प्रशिक्षित दिमाग और जज की नैतिक जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो AI समय बचा सकता है और कानूनी काम के कुछ पहलुओं को ज्यादा आसान बना सकता है। जस्टिस विक्रम तेलंगाना में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जस्टिस नाथ ने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी किसी नोट का ड्राफ्टा बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे कानून बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि AI के गलत इस्तेमाल की वजह से न्यायिक व्यवस्था को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वह इससे पूरी तरह से दूरी बना ले। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि AI महज एक टूल है, और एक टूल को टूल ही रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज, सतीश चंद्र शर्मा और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य जज, जस्टिस अपारेष कुमार सिंह ने भी बात रखी।

ईरान ने कल गुजरने की इजाजत दी थी, 2-3 दिन में भारत पहुंचेंगे
एलपीजी ला रहे 2 भारतीय जहाजों ने होर्मुज पार किया

राहत

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। खाड़ी देशों से LPG लेकर आ रहे भारत के दो जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारतीय झंडे वाले LPG कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने शनिवार होर्मुज स्ट्रेट पार किया। दोनों जहाज कुल 92,700 टन LPG लेकर भारत आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनके अगले 2–3 दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है। ये

दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे, जो मिडिल-ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे। इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शुक्रवार को कहा था कि ईरान ने कई भारतीय जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितने जहाजों को अनुमति दी गई।

» (शेष पेज 04 पर)

5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू

सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं, सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देशभर में छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा

अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 23% बढ़ीं

ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AAA के मुताबिक देश में गैस की औसत कीमत बढ़कर 3.68 डॉलर प्रति गैलन हो गई है, जो 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद करीब 23 प्रतिशत ज्यादा है। तेल बाजार में भी तेजी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड 103.14 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 98.71 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रोक दी है। दुनिया के कुल व्यापारिक कच्चे तेल का करीब 20 प्रतिशत इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है, इसलिए इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है।

"इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। उन्होंने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमलों की तारीफ करते हुए कहा कि संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है। काट्ज ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।

92,700
टन दोनों जहाज एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं।

ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस लावन अब भी कोच्चि में खड़ा

ईरानी नौसेना का जहाज IRIS लावन अभी भी केरल के कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज के गैर-जरूरी क्रू सदस्य और भारत में फंसे अन्य ईरानी नागरिक चार्टर्ड फ्लाइट से अपने देश लौट गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि IRIS लावन को तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि में डॉक किया गया था। ईरान ने 28 फरवरी को जहाज के लिए आपात डॉकिंग की अनुमति मांगी थी और भारत ने 1 मार्च को इसकी मंजूरी दी।

लॉरेंस गैंग की बादशाह को गोली मारने की धमकी
टटीरी सॉन्ग पर लिखा- हरियाणवी संस्कृति खराब करने की कोशिश की

तमसा संकेत, एजेंसी

पानीपत। हरियाणा के पानीपत में शनिवार को असंध रोड स्थित मनी एक्सचेंज सेंटर पर बदमाशों ने फायरिंग की। घटना के बाद रणदीप मलिक के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में लिखा कि यह हवाला के जरिए देश का पैसा बाहर भेज रहा था। इसे पहले भी चेतावनी दी गई थी। पोस्ट के आखिरी में बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह को टटीरी सॉन्ग को लेकर धमकी दी गई। पोस्ट में लिखा- बादशाह, तूने हरियाणा की संस्कृति खराब करने की कोशिश की है। पहले 2024 में तेरे क्लब पर तुझे ट्रेलर दिखाया था, अब की बार सीधा तेरे माथे में गोली मारेंगे। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। पानीपत के असंध रोड पर मनी एक्सचेंज सेंटर हस्त फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। गोलियां दुकान के शीशे पर लगीं। दुकान पर कार्यरत हरीश कुमार ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 3:15 बजे वह महिला कर्मचारी प्रीति के साथ मौजूद था। दुकान के मालिक गौरव मिगलानी किसी काम से बाहर गए हुए थे।

» (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज़

बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक

बेगूसराय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बेगूसराय पहुंची। सभा को संबोधित कर करते हुए CM ने कहा, 'हम लोगों की सरकार आपके लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र भी लगातार मदद कर रही है। 2005 में NDA की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है। हमारी सरकार आने से पहले पुरानी वाली सरकार ने बुरा हाल कर रखा था।

अडाणी पावर प्लांट में आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़

सिंगरौली। सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित अडाणी पावर प्लांट में शनिवार सुबह मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए मजदूरों ने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। सामने आए वीडियो में दूर से काले धुएं का बड़ा गुबार नजर आ रहा है। प्लांट के अंदर एक साइट के नीचे भी आग लगी हुई है। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, प्लांट में काम करने वाले मजदूर लल्लन सिंह की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। मृतक मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला था।

उबर राइडर ने लड़की से छेड़छाड़ की

नई दिल्ली। दिल्ली में युवती से उबर राइडर ने छेड़छाड़ की है। पीड़ित ने बताया कि घटना 12 मार्च की रात की है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी FIR नहीं दर्ज हुई है। युवती की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक 12 मार्च की रात करीब 1.28 बजे उसने रोहिणी सेक्टर 15 से पीतमपुरा के एमपी ब्लॉक मार्केट के लिए उबर बाइक बुक की थी।

अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के उत्तर में 'पंडित' शब्द का विकल्प

हंगामा

तमसा संकेत, एजेंसी

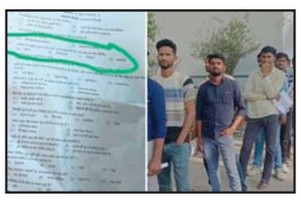

लखनऊ। यूपी एसआई परीक्षा के पहले दिन एक प्रश्न ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर रखा है। दरअसल एक प्रश्न के उत्तर में एक जाति को शामिल कर दिया गया है। परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न में अवसर के अनुसार बदलने वाला' इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था। इसके लिए चार विकल्प दिए गए थे। इसमें चार विकल्पों में पहला है सदाचारी, दूसरा पंडित, तीसरा अवसरवादी और चौथा निष्कपट। तीन विकल्प तो किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के होते हैं लेकिन एक विकल्प एक जाति से जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न पत्र के बाहर आते ही यह तेजी से वायरल हुआ। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा में 5,31,765 अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती परीक्षा की

शुचिता भंग करने के प्रयास करने वाले सोशल मीडिया एकाउंट्स के खिलाफ लखनऊ में कुल सात केस दर्ज किए गए हैं। एसटीएफ ने आगरा से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी फर्जी प्रश्न पत्र भेजकर अभ्यर्थियों से ठगी कर रहा था। मामले में एसटीएफ की तफ्तीश जारी है। मामले में और भी कार्रवाई हो सकती है। इसी दौरान टेलीग्राम पर "यूपी एसआई यूपी पुलिस-2026", "रिजल्ट पैनल प्राइवेट" और "यूपी एसआई परीक्षा प्रश्नपत्र-2026" नाम से चैनल चलाकर उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे।

पंजाब को कॉमेडी सीएम नहीं चाहिए : शाह
बीजेपी होती तो करतारपुर साहिब पाक में न होता, अकेले चुनाव लड़ेंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

मोगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मोगा में बदलाव रैली में पहुंचे गृह मंत्री ने केसरी रंग की पगड़ी पहनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पगड़ी देश पर गुरुघर के कर्ज का प्रतीक है। शाह ने यह भी कहा कि 2027 में भाजपा पंजाब में सरकार बनाएगी। शाह के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि अकाली दल से गठबंधन के अभी कोई आसार नहीं हैं। शाह ने वादा किया कि BJP की सरकार बनी तो 2 साल में ही नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शाह ने ये भी कहा कि पंजाब में कॉमेडी करने वाला सीएम नहीं बल्कि काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। शाह ने पंजाब CM भगवंत मान को AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का ATM बताया। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारे के वक्त भाजपा की सरकार होती तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में होता।

"वहीं, रैली में आने से पहले शाह ने ट्वीट कर कहा- पंजाब का हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। क्योंकि जवानों, किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध पंजाब की पवित्र भूमि को आप-दा सरकार ने करप्शन, ड्रग्स और अपराध में डुबो दिया है। रिमोट कंट्रोल वाली आप-दा सरकार में पंजाब से लॉ एंड ऑर्डर और विकास नदारद हैं। आज मोगा में पंजाब के बहनों-भाइयों से संवाद के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने रैली में परफॉर्म किया। सिंगर ने कहा कि वह सभी पार्टियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए मुआवजा देने का वादा किया है।"

गृहमंत्री के भाषण की बड़ी बातें

- **गुरु तेग बहादुर न होते तो देश में कोई हिंदू न होताः** गृहमंत्री ने कहा- जो मेरे सिर पर जो पगड़ी दिख रही है, वह पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर कहे गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो देश में कोई हिंदू बचा न होता।
- **हम होते तो करतारपुर साहिब पंजाब में होताः** शाह ने कहा- 1984 के सिख दंगों के खिलाफ हमारी सरकार ने 350 केस दर्ज किए। कांग्रेस ने एक भी नेता जेल में नहीं डाला। हमने डाला। हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिख बचकर आए, उन्हें नागरिकता हमने दी। करतापुर कोरिडोर हमने बनाया। जब बंटवारा हुआ, हम उस समय होते तो करतारपुर साहिब को जाने न देते।
- **AAP-कांग्रेस गुमराह कर रहेः** शाह ने कहा- AAP सरकार और राहुल बाबा (राहुल गांधी) किसानों को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल ने फोन किया कि जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है, उससे किसानों को नुकसान होगा। पंजाब के किसानों, इनकी बात न सुनना। ये झूठ बोलते हैं। डब्ल्यूटीओ में 2013 में एमएसपी न दिया जाए, ऐसा करार वे करके आए। भगवान भला करे देश की जनता का कि 2014 में इन्हें निकाल दिया। 2017 में इसकी कन्फर्मेशन करने की बारी आई तो मोदी ने इनकार कर दिया।

टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, ममता की मंत्री बोलीं- मुझे ईंट मारी गई
पीएम मोदी की रैली में झड़प

विवाद

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है। गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान मुझ पर ईंट मारी गई। भाजपा गुंडा नहीं है, हत्यारी है। मंत्री पंजा का यहीं पर घर है। कोलकाता में अपने संबोधन कि दौरान पीएम ने कहा कि जंगलराज वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये निर्मम वाली सरकार का अंत करीब आ गया है। पीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर

कम्यूनिस्ट अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे और अपनी जेब भरते रहे। मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले, नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करे। दरअसल, पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास किया। उनके साथ मंच पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के गवर्नर आरएन रवि मौजूद रहे।

» (शेष पेज 04 पर)

"पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू बंगाल आईं। उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन इस सरकार ने उनका विरोध किया, क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर हैं, इन्हें उनका सम्मान मंजूर नहीं थी।"

पीएम ने कहा- बंगाल में एक ही चर्चा है कि बदलाव चाहिए

पीएम ने कहा कि पूरे बंगाल में एक ही चर्चा है कि बदलाव चाहिए, जब-जब इस भूमि पर चुनौती आई तब तब यहां के लोगों ने सामना किया है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती।

पीएम की स्पीच की 5 बड़ें बातें...

- भाजपा बंगाल को महान बनाने के लिए काम करेगी। सही नीतियों और नीयत से राज्य में विकास होगा और किसानों, युवाओं, व्यापारियों और छात्रों को फायदा मिलेगा।
- राज्य की मौजूदा सरकार केंद्र की योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने देती और कटमनी के कारण गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता।
- बंगाल में युवाओं को न अच्छी शिक्षा मिल रही है और न रोजगार। किसान भी परेशान हैं और कई लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।
- राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं चिंता का विषय हैं। भाजपा सरकार आने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और अब टीएमसी ने राज्य पर शासन किया, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। भाजपा सरकार बनने पर सबका साथ, सबका विकास होगा और सबका हिसाब किया जाएगा।

सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया
170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा, लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) हटा दिया। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, सोनम ने NSA एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे सोनम की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंचीं। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। फिर दोपहर सवा एक बजे पत्नी के साथ एक निजी गाड़ी से जेल से निकले। दरअसल, सोनम के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी।

दो दिन पहले वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था लद्दाख के लिए ईमानदार संवाद आवश्यक है। मैंने एक्टिविज्म से दूरी नहीं बनाई है। लद्दाख के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले जैसी ही है। इसका उद्देश्य लद्दाख के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी भविष्य है।

सम्पादकीय

पूरा हुआ अविश्वास प्रस्ताव का मकसद

बुधवार, 11 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया, गिरना ही था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विपक्ष भी इस बात को जानता था कि यह प्रस्ताव सफल नहीं होगा। लेकिन जिस उद्देश्य से विपक्ष ने इस प्रस्ताव को पेश किया, उसमें काफी हद तक उसे सफलता मिल गई है। लोकसभा में अध्यक्ष की आसंदी दलगत राजनीति से ऊपर होती है और उसकी निगाह में पक्ष-विपक्ष का महत्व एक समान होता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि लोकसभा की कार्रवाई में पक्षपात न रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को जनता ही चुनकर भेजती है, इसलिए दोनों की आवाज को बराबरी से स्थान मिले, यह जरूरी है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाए और बहुमत के कारण सारे फैसले सत्ता पक्ष के हक में लिए जाएं, तो यह केवल विपक्षी सांसदों के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि उनके क्षेत्र के करोड़ों मतदाताओं के साथ नाइंसाफी है। अगर जनता के साथ नाइंसाफी होती है, तो फिर लोकतंत्र ही अपना अर्थ खो देता है। इस अर्थ को बचाने के लिए बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष के लिए शायद यही आखिरी रास्ता भी बचा था कि किसी तरह अपनी बात को आधिकारिक तौर पर दर्ज करा सके। ध्यान रहे कि संसद सत्र के पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। पहले जनरल मनोज नरवणे की किताब के जिक्र पर उन्हें बोलने से रोका गया और नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद एपस्टीन फाइल्स के जिक्र पर फिर से राहुल गांधी की बात को दबाया गया। उनके साथ-साथ कई और सांसदों को बोलने से रोका गया। इन सब में बार-बार निगाहें ओम बिड़ला की तरफ ही जाती थीं कि वे नीर-क्षीर विवेक से निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने भी संसदीय नियमों का हवाला देते हुए बार-बार विपक्ष को ही टोका। हद तो तब हो गई जब लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की महिला सांसदों पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने आ गई थीं और इससे प्रधानमंत्री को खतरा था, लिहाजा उन्होंने नरेन्द्र मोदी को सदन में आने से मना कर दिया।

बता दें कि इस पर चर्चा के दौरान किरण रिजीजू और अमित शाह जैसे नेताओं ने जो बातें कहीं, उन पर विपक्ष ने फिर विरोध प्रदर्शन किया और इस के बीच ही आसंदी पर बैठे जगदंबिका पाल ने ध्वनिमत कराया जिसमें ये प्रस्ताव गिर गया। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिड़ला ने 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार' दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चर्चा शुरु होने से एक दिन पहले ही एक वीडियो संदेश में ओम बिड़ला की तारीफ कर बता दिया कि वे उनका हर हाल में बचाव करेंगे। वहीं अमित शाह ने कहा कि, 'क़रीब चार दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है। यह संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए अफ़सोसजनक घटना है। स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने उस पद को एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका में रखा है। आपने (विपक्ष) मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के बादल उठा दिए। हम भी विपक्ष में रहे लेकिन कभी भी बीजेपी और एनडीए लोकसभा स्पीकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। हमने स्पीकर के पद की गरिमा का संरक्षण करने का काम किया। इसके बाद आदतन वे राहुल गांधी पर बोलने लगे और कहा कि फ्लाइंग किस करोगे, आंख मटकाओगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठा रहे हो। ये किस तरह से आचरण की बात करते हैं। हालांकि, इस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया तो अमित शाह ने कहा कि ऐसा कोई शब्द हो जो असंसदीय हो, तो उसे कार्यवाही से हटा सकते हैं। अपने बयान में अमित शाह ने धड़ल्ले से साला अपशब्द का भी इस्तेमाल किया, इससे पहले दिसंबर 2025 में भी वे सदन के भीतर साला बोल चुके हैं। तो राहुल गांधी को आचरण की सीख देने वाले अमित शाह के आचरण पर ओम बिड़ला और नरेन्द्र मोदी क्या कहते हैं, इसका इंतजार है, क्योंकि अब तक तो इन दोनों ने इस पर न अफसोस न आपत्ति दर्ज कराई है। तो क्या मौन इनके स्वीकार का लक्षण है। बहरहाल अमित शाह ने सत्र के दौरान राहुल की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए, जबकि वे जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी भी चलती संसद को छोड़कर विदेश गए और जब देश में रहे, तब भी अहम चर्चाओं में शामिल नहीं हुए। वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव ओम बिड़ला के खिलाफ था, तो उस पर बात होनी थी, लेकिन उन्हें तो निंदा से परे बताने का काम अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। वैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से स्पीकर को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संसद की गरिमा की रक्षा के लिए लाया गया है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है।

भारत में बेहतर शासन प्रणाली के लिए चीनी मॉडल को अपनाइये

> **चीन की शासन प्रणाली, मुख्यतः सीपीपी (सीसीपी) के एकदलीय नेतृत्व वाली, के प्रमुख फायदे आर्थिक विकास, स्थिरता और निर्णय दक्षता पर केंद्रित हैं। ये फायदे मुख्य रूप से चीन के विशाल आकार, विकास चरण और सांस्कृतिक संदर्भ के कारण उभरते हैं।**

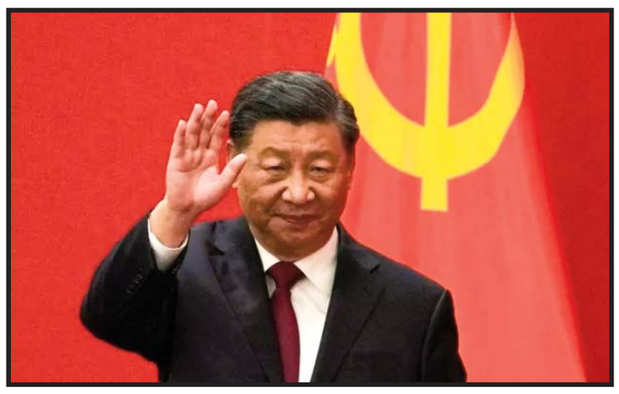

भारत का पड़ोसी देश चीन, रणनीतिपूर्वक पश्चिमी देशों के लोकतांत्रिक षड्यंत्रों को मात देता आया है। इससे भी भारत बहुत कुछ सीख सकता है। कहा भी जाता है कि अमेरिका को वकील और चीन को इंजीनियर चलाते हैं। यह पश्चिमी लोकतंत्र पर बहुत बड़ा व्यंग्य भी समझा जाता है। चूंकि देर-सबेर भारत का मुकाबला चीन से ही होना है तो फिर क्यों नहीं भारत चीनी शासन प्रणाली को अपनाकर खुद को उस जैसा ही मजबूत बना ले। ऐसा इसलिए कि अब्राहम परिवार का सूत्रधार अमेरिका, ईसाई-यहूदी-इस्लामिक मुल्कों में भारत को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। वह ब्रिटेन के ही तर्ज पर यहां जातीयता और धर्मनिरपेक्षता को हवा देगा। पक्ष-विपक्ष को शह देकर भटकाएगा। लोकतंत्र और भागीदारी की आड़ में एक दूसरे के विरुद्ध कुचक्र चलवायेगा। इसलिए भारत-चीन की दोस्ती उतनी क्षति नहीं पहुंचाएगी जितनी कि पश्चिमी देशों की दोगलागिरी पहुंचा चुकी है। वहीं, पश्चिमी कुचक्रों यानी अमेरिकी-यूरोपीय षड्यंत्रों से एशिया को महफूज रखने के लिए, सावधान रहकर रूस-भारत-चीन को समझदारीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता और अमेरिकी दादागिरी को यदि समय रहते काबू नहीं किया गया तो ईसाई, यहूदी व इस्लामिक देश आपस में ही लड़-कट मरेंगे या फिर भारत के अकूत प्राकृतिक संसाधनों पर हमलावर होंगे। इनका अतीत भी यही चुगली करता है। अब समझिए, चीन जैसा प्रशासनिक मॉडल भारत में लाने के लिए सिर्फ़ "कदम" नहीं, पूरे संवैधानिक-राजनीतिक ढांचे की दिशा बदलनी पड़ेगी जिसका मतलब लोकतांत्रिक, बहुदलीय, संघीय और मौलिक अधिकार आधारित व्यवस्था को मूल रूप से बदलना है। इसे चरणबद्ध, यथार्थवादी (और जोखिम-सहित) रूप में नीचे दर्शा रहा हूँ। उससे पहले भारतीय लक्ष्य स्पष्ट करना होगा कि चीन से क्या कॉपी करना है और क्या नहीं! दरअसल, चीन की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- पहला, एकदलीय कम्युनिस्ट शासन, जहां वास्तविक सत्ता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के हाथ में होती है जबकि "पीपुल्स कांग्रेस" प्रणाली, जहाँ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस औपचारिक रूप से सर्वोच्च अंग है, के ऊपर व्यवहार में पार्टी सर्वोपरि रहती है। वहीं, सत्ता के अंगों में व्यावहारिक रूप से कोई सख़्त विभाजन नहीं बल्कि सब पर पार्टी का नेतृत्व मजबूत होता है। वहां बहुत सीमित राजनीतिक विपक्ष है. मीडिया-नागरिक समाज पर कड़ा नियंत्रण है, इसलिए ज्यादा सियासी उधेड़बुन में लोग नहीं फंसते हैं। अब भारत की मौजूदा बुनियाद समझते हैं। यहां संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय प्रतियोगिता दिखती है, संघीय ढांचा (केंद्र–राज्य) है, मौलिक अधिकार मिले हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और न्यायिक समीक्षा को महत्व दिया गया है। यहां सत्ता का आंशिक विभाजन है और "चेक्स ऐंड बैलेंस" भी है लेकिन नेताओं का कलह, अधिकारियों की मनमर्जी और जनता के स्वार्थी सिरफुटौव्वल का ठोस विकल्प देश को चाहिए। इसलिए कोई भी "चीन आधारित" मॉडल दो रास्तों में से होगाः पहला, "कठोर" रास्ताः चीन जैसा लगभग-एकदलीय, केंद्रीकृत, अधिकार-सीमित मॉडल, और दूसरा, "मृदु" रास्ताः चीन से प्रशासनिक-नीतिगत दक्षता के सबक लेकर लोकतंत्र को बरकरार रखना। इस हेतु संवैधानिक स्तर पर बड़े परिवर्तनों के कदम उठाने होंगे। यदि कोई चीन-नुमा राजनीतिक मॉडल चाहता है तो सैद्धांतिक कदम भी उठाने होंगे। संविधान की मूल संरचना बदलने की कोशिश करनी होगी। अनुच्छेद 14, 19, 21, 25 आदि मौलिक अधिकारों को सीमित/पुनर्परिभाषित करना करना होगा। अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म-स्वतंत्रता पर व्यापक नियंत्रण संभव करने हेतु।वहीं, परोक्ष कारोबार बन चुकी न्यायिक समीक्षा और "बेसिक स्ट्रक्चर" सिद्धांत को कमज़ोर करने या हटाने के लिए व्यापक संशोधन करना होगा। खासकर, बहुदलीय व्यवस्था से "प्रभुत्वशाली दल" या व्यवहारिक-एकदलीय ढांचा तैयार करना होगा ताकि एक मुख्य राष्ट्रीय पार्टी को संवैधानिक या कानूनी रूप से "राष्ट्र-निर्माण की धुरी" जैसा दर्जा मिले जबकि अन्य दलों को औपचारिक-सहयोगी पर गैर-प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। चीन में भी 8 छोटे दल सीसीपी (CCP) के अधीन हैं। ऐसा होने से जातीय व धार्मिक पार्टी और पारिवारिक वंशवाद का सफाया होगा। वहीं, चुनावी क़ानूनों में बदलाव से पार्टी के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कम होगी और "अनुमोदित विपक्ष" की दिशा तय होगी। भारत में क्षेत्रवादी सियासत से जिस तरह से राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाई जा रही है, उससे बेहतर है कि केंद्र में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो। इस हेतु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन कर ज़्यादातर महत्त्वपूर्ण विषय जैसे- शिक्षा, पुलिस, कृषि, भूमि, स्वास्थ्य को केंद्र सूची या संयुक्त सूची में लाना जरूरी है। वहीं राष्ट्रपति/केंद्र सरकार को राज्यों की नीतियों पर व्यापक वीटो देने होंगे और गवर्नर की भूमिका और मजबूत करना होगा; साथ ही, आपातकालीन प्रावधानों का दायरा बढ़ाना होगा। खासकर, संसद के ऊपर "पार्टी संरचना" की वास्तविक सर्वोच्चता लानी होगी। चीन की तरह पार्टी-संगठन (पॉलित ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी टाइप) को वास्तविक नीति-निर्माता बनाना होगा और संसद को मुख्यतः अनुमोदन मंच में बदलना होगा। साथ ही सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं में पार्टी-सेल/कोर-कमेटी अनिवार्य करके निर्णयों को पार्टी लाइन से बाँधना होगा। क़ानूनी-राजनीतिक यथार्थ के दृष्टिगत यह सब भारत की "बेसिक स्ट्रक्चर" न्यायिक व्याख्या से टकराएगा; इसलिए व्यवहार में ऐसा मॉडल लागू करना प्रायः असंवैधानिक क्रांतिकारी बदलाव या बहुत दीर्घकालिक "क्रमिक परिवर्तन" के बिना संभव नहीं है। जहां तक प्रशासनिक और नीतिगत स्तर के "चीनी सबक" की बात है तो अगर लक्ष्य यह है कि चीन की "गवर्नेंस दक्षता" ली जाए और लोकतंत्र भी बरक़रार रहे तो अपेक्षाकृत व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। इस हेतु दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास योजनाएँ 20–30 वर्ष का औद्योगिक, तकनीकी और सैन्य-आर्थिक रोडमैप, जिसे दल बदलने पर भी मुख्यतः जारी रखा जाए। यही चीन की लांग-टर्म प्लानिंग की तरह होगा। वहीं, कैडर-आधारित नौकरशाही प्रबंधन के तहत वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के लिए सख़्त प्रदर्शन-मानक बनाना होगा न कि केवल वरिष्ठता के आधार पर। वहीं स्थानीय स्तर पर "एकीकृत कमांड" मॉडल के तहत जिला/ज़िले से नीचे स्तर पर बहु-विभागीय टीम को एक नेता के तहत रखना होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर नियंत्रित-भागीदारी रखनी होगी।

कमलेश पांडेय

जन सुराज का...

बाबूलाल नागा

बहुजन चेतना के शिल्पीः कांशीराम

15 मार्च का दिन भारतीय समाज के लिए हमेशा विशेष रहेगा क्योंकि इसी दिन एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक समझ को गहराई से झकझोरा। कांशीराम केवल एक नेता नहीं थे, वे बहुजन समाज की जागरूकता और सशक्तिकरण के अद्वितीय प्रेरक थे। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि समाज में समानता और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष और संगठित प्रयास ही आवश्यक हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था, और उनका बचपन गरीबी और सामाजिक असमानताओं के बीच बीता। उन्होंने देखा कि समाज के कमजोर वर्ग शिक्षा और अवसर की कमी के कारण हमेशा पिछड़ते रहे।

इन अनुभवों ने उनमें एक गहरी समझ और सामाजिक न्याय की चेतना को जन्म दिया। उनके विचारों की नींव डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित थी, जिन्होंने हमेशा वंचितों के अधिकार और समानता की बात की। कांशीराम ने यही समझा कि जब तक बहुजन समाज संगठित नहीं होगा, तब तक सत्ता में उसकी हिस्सेदारी केवल आकांक्षा ही रहेगी। उनकी सामाजिक पहलें हमेशा सैद्धांतिक विचारों से आगे बढ़कर व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी थीं। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता को समाज के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन माना। सरकारी नौकरियों और संस्थानों में संगठित प्रयासों के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज को यह विश्वास दिलाया कि उनका हक केवल मांगने से नहीं, बल्कि संगठित होकर उसे हासिल करने से सुनिश्चित होता है। उनका यह दृष्टिकोण केवल विरोध तक सीमित नहीं था, वे चाहते थे कि समाज के हर सदस्य को आत्मसम्मान और अधिकार मिले। कांशीराम का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को यह सिखाया कि जागरूकता ही शक्ति है। उनका मानना था कि यदि समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए, तो कोई भी असमानता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि केवल आक्रोश करना या विरोध करना पर्याप्त नहीं है; समाज को संगठित होकर रणनीतिक रूप से काम करना होगा। उनकी दूरदर्शिता ने बहुजन समाज को नई पहचान दिलाई। उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल और सामाजिक समझ का प्रयोग करके समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान के लिए एक मंच दिया।

उनके प्रयासों से लाखों लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक हुए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज के पिछड़े वर्ग शिक्षा, नौकरी और सामाजिक अवसरों में पीछे न रहें, और उन्हें यह एहसास हो कि उनका स्थान समाज और राष्ट्र की प्रगति में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य वर्ग का। कांशीराम के विचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल वर्तमान की समस्याओं तक सीमित नहीं थे। वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी रास्ता दिखाना चाहते थे। उन्होंने यह समझा कि सामाजिक बदलाव केवल तत्कालिक नीतियों से नहीं आता, बल्कि यह तब संभव है जब समाज के हर सदस्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और समानता, न्याय तथा सम्मान के मूल्यों को आत्मसात करे। उनकी यह सोच आज भी हमारे सामने मार्गदर्शक है, क्योंकि समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमें केवल उनके व्यक्तित्व को याद नहीं करना चाहिए। हमें उनके विचारों, उनकी सामाजिक सोच और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। कांशीराम ने यह दिखाया कि समाज में सच्चे बदलाव के लिए राजनीतिक सत्ता का होना जरूरी नहीं बल्कि संगठन, जागरूकता और शिक्षा का होना आवश्यक है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि समाज के कमजोर वर्गों को संगठित करके ही असमानता और अन्याय के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनका संघर्ष केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा; उनकी विरासत आज भी बहुजन समाज को दिशा देती है। उनके आदर्श यह सिखाते हैं कि संगठन, शिक्षा और जागरूकता का संयोजन ही सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी ताकत है। 15 मार्च के दिन उनकी जयंती इस प्रेरणा का प्रतीक है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए और समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। कांशीराम की सोच और उनके सामाजिक कार्य आज भी हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन किसी व्यक्तिगत संघर्ष से नहीं आता, बल्कि संगठित और सतत प्रयास से आता है। उनका जीवन यह बताता है कि बहुजन समाज की चेतना ही समाज को सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने की कुंजी है। उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि समानता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। कांशीराम की जयंती केवल स्मृति का दिन नहीं है, बल्कि बहुजन चेतना और सामाजिक न्याय की मशाल जलाने का दिन है

निवेशकों को...

सौरभ वार्ष्णेय

तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स का गिरनाः क्या अर्थतंत्र में महासंकट के संकेत?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब भी ऊर्जा संकट गहराता है, उसका सीधा असर वित्तीय बाजारों और आम लोगों की जेब पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी तथा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक गिरावट की ओर गया है। यह गिरावट केवल बाजार की सामान्य हलचल नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़े संभावित बड़े संकट का संकेत भी हो सकती है। वहीं जब मैं इस लेख को लिख रहा हूं तो सेंसेक्स और निफ्टी काफी हद तक गिर चुका है। ऐसे में सरकार के कहने के बावजूद जनमानस इस युद्ध के बीच ऊर्जा का भंडार भरकर रखना चाहता है. यह युद्ध क्या पटकथा लिखेगा, कोई नहीं जानता क्योंकि रुस-युक्रेन युद्ध भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ। भारत जैसे देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। जब वैश्विक स्तर पर तेल-गैस की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका असर सीधे महंगाई, उत्पादन लागत और व्यापार संतुलन पर पड़ता है। उद्योगों की लागत बढ़ती है, परिवहन महंगा होता है और अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। निवेशकों को भी यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार का गिरना इसी चिंता का प्रतिबिंब है। निवेशक भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। विदेशी निवेशक भी जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से पूंजी निकालते हैं जिससे बाजार में गिरावट और तेज हो जाती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की गति पर पड़ सकता है। ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू राजकोषीय दबाव भी है। सरकार को महंगाई नियंत्रित करने के लिए करों में कटौती, सब्सिडी या अन्य राहत उपाय देने पड़ सकते हैं। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। साथ ही यदि आयात बिल बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है जो आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाता है हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाजार हमेशा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति का सटीक दर्पण नहीं होता। कई बार वैश्विक परिस्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव या निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से भी बाजार अचानक गिर सकता है। इसलिए सेंसेक्स की गिरावट को तुरंत ₹महा संकट₹ मान लेना भी उचित नहीं होगा लेकिन इसे एक चेतावनी संकेत जरूर माना जाना चाहिए। ऐसे समय में सरकार और नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की है। देश को तेल-गैस के आयात पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रणनीतिक भंडार बढ़ाने जैसी नीतियों पर तेजी से काम करना होगा। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देकर बाजार का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। अंततः कहा जा सकता है कि तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स की गिरावट केवल बाजार की घटना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की याद दिलाती है। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो यह संकट अवसर में भी बदल सकता है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

राजेश कुमार पासी

राष्ट्रपति का बार-बार अपमान क्यों

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीति होती है लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है । राजनीतिक दल भी उसे किसी दल विशेष से नहीं जोड़ते हैं। हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को सबसे ऊपर रखा है और वो एक तरह से राष्ट्र प्रमुख माना जाता है। देश का पूरा प्रशासन उनके ही नाम पर चलाया जाता है जबकि उनका प्रशासन में कोई दखल नहीं होता। संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियां, वास्तव में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की होती हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास कई अधिकार हैं जहां वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो संसद द्वारा पास किये गए विधेयक को दोबारा विचारार्थ हेतु वापस भेज सकते हैं । इसके अलावा जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति कैबिनेट की रबर स्टैंप के रूप में ही काम करते हैं। दूसरी तरफ सच है कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है । प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति ही देश का शासक होता है. इसी आधार पर राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाता है। जब राष्ट्रपति का प्रशासन में सीधा दखल नहीं है तो उन्हें राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। जब से द्रोपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, उनका कई बार अपमान किया जा चुका है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि उनका इस पद पर आना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आदिवासी समाज से आने वाली द्रोपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं। देखा जाए तो मोदी सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाकर देश के आदिवासी समाज को सम्मानित करने का काम किया है। देश का आदिवासी समाज इस बात पर गर्व करता है कि उनके समुदाय की एक महिला इस समय देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। एक तरह से ये भी आदिवासियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए लेकिन पिछले कुछ समय से उन पर भी राजनीति की जा रही है। अभी तक केवल उनका मजाक बनाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो उनका और उनके पद का जबरदस्त अपमान किया है। जब राष्ट्रपति एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बंगाल गयी थीं तो ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरना दे रही थी। वो राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और न ही उनकी अगवानी की। इसके अलावा उन्होंने अपने किसी मंत्री को भी उनकी अगवानी करने के लिए भेजा। देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के आगमन पर किये जाने वाले प्रोटोकॉल का बड़ा उल्लंघन है। ममता बनर्जी अपने अक्खड़पन और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के साथ उनका व्यवहार समझ से परे है। ऐसा लगता है कि एसआईआर का विरोध करते-करते वो इतना बौखला गईं हैं कि उन्हें सही और गलत का पता ही नहीं चल रहा है। उनकी बौखलाहट की वजह यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों के जरिये इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है। ममता बनर्जी अपने आपको असहाय महसूस कर रही हैं, इसलिए धरना देने बैठी और फिर खुद ही उठ गईं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने बंगाल के दार्जलिंग में गयी थी, इसके बाद वो विद्यानगर गईं और उन्होंने वहां सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में मेरे साथ होना चाहिए था। उन्होंने कहा, "मैं बंगाल की बेटी हूँ, फिर भी मुझे यहां आने की अनुमति नहीं है। ममता मेरी बहन जैसी हैं, पता नहीं, शायद वो मुझसे नाराज हैं। शायद इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है।" महामहिम राष्ट्रपति इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करती हैं. वो बेहद शांत स्वभाव की हैं। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया है। उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर मूल स्थान का दौरा किया था, इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम का आयोजन विद्यानगर में किया जाना था लेकिन उसका स्थान बदलकर बागडोगरा के गुसाईपुर में कर दिया गया । अजीब बात यह है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी जिसके कारण स्थान बदलना पड़ा। राष्ट्रपति को गुस्सा यह था कि आयोजन स्थल बहुत छोटा और दूर था जहां लोग पहुंच नहीं पाए। राष्ट्रपति के द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद भाजपा ने टीएमसी पर हल्ला बोल दिया है। भाजपा ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए कहा है कि एक आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है और टीएमसी को इस अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मुद्दे ने भाजपा को बंगाल के हालात पर बोलने का मौका दे दिया है। भाजपा ममता बनर्जी की विरोधी पार्टी है, उसे हटा भी दिया जाए तो मुद्दा छोटा नहीं होता। ममता बनर्जी ने जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति को जवाब दिया है, उससे पता चलता है कि उनका अपमान अंजाने में नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझकर किया गया है। उन्होंने एक फ़ोटो दिखाकर कहा है कि राष्ट्रपति को तब अपमान महसूस नहीं हुआ था । वास्तव में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' पुरस्कार देने राष्ट्रपति महोदया उनके घर गईं थीं। जब उन्होंने खड़े होकर आडवाणी जी को पुरस्कार दिया तो वो बैठे हुए थे और वहां मोदी जी भी उनकी बगल में बैठे थे। इसके अलावा भी उस समय वहां कई नेता उपस्थित थे, जो वहां कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ममता बनर्जी के कहने का मतलब यह था कि आप राष्ट्रपति होकर वहां खड़ी थी और वहां सब बैठे हुए थे लेकिन तब आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ। वास्तव में ममता बनर्जी जानबूझकर अंजान बन रही हैं। भारत रत्न या अन्य पुरस्कार देते समय राष्ट्रपति खड़े रहते हैं और पुरस्कृत व्यक्ति भी खड़े होकर पुरस्कार ग्रहण करता है। उन दोनों के अलावा सब बैठे रहते हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल है। जब पुरस्कृत व्यक्ति खड़े होने में असमर्थ होता है, तब भी राष्ट्रपति खड़े होकर उसे पुरस्कृत करते हैं। राष्ट्रपति भवन में भी कई बार देखा गया है, जब पुरस्कृत व्यक्ति चलकर उनके पास नहीं जा सकते तो राष्ट्रपति खुद चलकर उनकी कुर्सी पर ही पुरस्कार प्रदान करते हैं। ये फोटो दिखाकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि उन्होंने जानबूझकर उनका अपमान किया है।

किसी भी प्लेयर पर जुर्माना नहीं : पीसीबी

दावा था- 50-50 लाख पेनल्टी लगेगी, टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-8 से बाहर हुआ था पाक

- भारत ने कोलंबो में खेले गए ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 61 रन से हराया था।
- पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर-8 मैच में जीतकर भी टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था।

लाहौर, एजेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शनिवार को कहा है कि किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। बोर्ड के प्रवक्ता अमीर मीर ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा- 'किसी खिलाड़ी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, लेकिन बोर्ड खिलाड़ियों के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने पर विचार कर रहा है, ताकि उन्हें अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। इंग्लैंड ने करीबी मुकाबला हरा दिया। इसके बाद सेमीफाइनल की उम्मीदें दूसरे मैचों के नतीजों पर टिक गईं। श्रीलंका पर करीबी जीत के बावजूद रन रेट खराब रहा। इस कारण न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज की। इसके बाद USA को हराया। श्रीलंका की परिस्थितियों और स्पिन गेंदबाजों के दम पर भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन टीम 61 रन से हार गई। पाकिस्तान फिर नामीबिया को आखिरी मैच हराकर सुपर-8 स्टेज में पहुंचा। सुपर-8 स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुल गया।

नेशनल प्लेयर्स को हर महीने लाखों रुपए मिलते हैं

पाकिस्तान में नेशनल टीम का हिस्सा प्लेयर्स को 4 कैटेगरी में सैलरी मिलती है। ए कैटगरी में करीब 65 लाख, बी कैटेगरी में 45 लाख, सी कैटेगरी में 20 लाख और डी कैटेगरी में 12.50 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। हालांकि, जुलाई 2025 से जून 2026 के पिछले कॉन्ट्रैक्ट में PCB ने किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी में नहीं रखा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सेंट्रेल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मासिक रिटेनर के अलावा मैच और दौरे की फीस तथा जीत के बोनस मिलते हैं। प्लेयर्स को बोर्ड के लोगो स्पॉन्सरशिप समझौते से भी हिस्सा मिलता है।

श्रीलंका पर जीत के बावजूद बाहर हुआ पाकिस्तान

पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज की। इसके बाद USA को हराया। श्रीलंका की परिस्थितियों और स्पिन गेंदबाजों के दम पर भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन टीम 61 रन से हार गई। पाकिस्तान फिर नामीबिया को आखिरी मैच हराकर सुपर-8 स्टेज में पहुंचा। सुपर-8 स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुल गया।

स्पिनर उस्मान तारीक ने 10 विकेट लिए

पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 383 रन बनाए। सईम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम और उस्मान खान 100 रन भी नहीं बना सके। स्पिनर उस्मान तारीक ने 10 विकेट लिए, जबकि बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा।

दावा- हर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर 50 लाख रुपए का जुर्माना

12 दिन पहले 2 मार्च को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि टी20 वर्ल्डकप में अंतिम-4 में जगह बनाने में विफल रहने के बाद हर पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

सूर्या-गंभीर वर्ल्डकप ट्रॉफी लेकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे

हनुमान मंदिर जाने पर कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया था

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर शनिवार को टी-20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। यहां दोनों ने भगवान गणेश के दर्शन कर टीम की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया।

इससे पहले 8 मार्च को चैंपियन बनने के बाद उन्होंने ट्रॉफी के साथ अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए थे। खिलाड़ियों के मंदिर जाने पर पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद कीर्ति आजाद ने सवाल भी उठाए थे। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा भी 13 मार्च को जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे और माता रानी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। टी-20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक ने अपनी यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं और कैप्शन लिखा- जय माता दी। फोटोज में वे सफेद कुर्ता-पायजामा पहने, माथे पर तिलक लगाए और हाथ जोड़कर दर्शन करते नजर आए।

अभिषेक ने टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। फाइनल से पहले के मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और लगातार 3 बार शून्य पर आउट हुए। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में उन्होंने महज 21 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था। इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन के अंतर से हराया और अपना टाइटल डिफेंड किया था। टीम इंडिया ने तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता था। ईशान किशन से एयरपोर्ट पर कीर्ति आजाद के कमेंट को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा, इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते। अच्छे सवाल आप लोग करिएगा, या कीर्ति आजाद क्या बोले? इस पर मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल करिए।

फास्ट न्यूज

एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण 18 साल बाद पद छोड़ेंगे

मुंबई। भारतीय मूल के शांतनु नारायण एडोबी के CEO का पद छोड़ रहे हैं। वे पिछले 18 साल से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। शांतनु ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में इसकी जानकारी दी है। हालांकि, वे तुरंत पद नहीं छोड़ेंगे। जब तक बोर्ड उनके उत्तराधिकारी की तलाश पूरी नहीं कर लेता, वे CEO बने रहेंगे। इसके बाद वे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।

मेटा में 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी

मुबंई। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में से 20% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। मेटा के पास 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 79,000 कर्मचारी थे, इस हिसाब से करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है। कंपनी यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ रहे अरबों डॉलर के खर्च और डेटा सेंटर्स की लागत को मैनेज करने के लिए उठा रही है। हालांकि, मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इन खबरों को 'काल्पनिक' बताते हुए फिलहाल किसी भी छंटनी से इनकार किया है। AI में निवेश की भरपाई के लिए छंटनी का प्लान

एकता कपूर लॉन्च करेंगी 'हुनर', कलाकारों को मिलेगा नया मंच

मुबंई। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े सितारे देने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर अब टैलेंट मैनेजमेंट की दुनिया में भी कदम रख रही हैं। उनके नेतृत्व वाली कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने नए टैलेंट मैनेजमेंट वेंचर 'हुनर' लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नई कंपनी खास तौर पर कलाकारों को निखारने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहानी कहने और परफॉर्मेंस के कल्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तनुश्री दत्ता का गंभीर दावा

कहा-शोबिज में कई कलाकारों का इस्तेमाल हो जाता है

नई दिल्ली, एजेंसी

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री (शोबिज) में नए कलाकारों के शोषण को लेकर गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मनोरंजन जगत में कई नए लोगों के साथ शोषण होता है और कुछ को तो देह व्यापार तक धकेल दिया जाता है। यूट्यूब चैनल मेरी सहेली के साथ बातचीत में तनुश्री ने कहा कि इंडस्ट्री में आने वाले कई नए लोगों को पहले तारीफों और बड़े वादों से आकर्षित किया जाता है। उन्होंने कहा, "किसी को कहा जाता है कि आप हीरोइन बनेंगे या बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन कई बार यही बातें आगे चलकर एक जाल की शुरुआत बन जाती हैं।" तनुश्री के अनुसार, कई लोग पहले नए कलाकारों की तारीफ करते हैं और फिर उन्हें अलग-अलग लोगों से मिलने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में कलाकारों को बहुत संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तनुश्री ने यह भी बताया कि उन्होंने एक एक्ट्रेस से दोस्ती खत्म कर दी थी, क्योंकि उस बातचीत में इंडस्ट्री में समझौते को सही ठहराने जैसी बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी से निजी रिश्ते में रहना उनकी इच्छा है तो वह अलग बात है, लेकिन वह अपनी जिंदगी का सौदा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, "मैं उस धंधे में नहीं हूं। मैं एक कलाकार हूं।"

मोबाइल के जमाने में लंबे समय तक पेजर यूज किया, तकनीक से ज्यादा काम पर फोकस

61 के हुए आमिर खान

नई दिल्ली, एजेंसी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। करीब चार दशक लंबे करियर में उन्होंने सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दीं, बल्कि अभिनय और कहानी कहने के तरीके को भी नई दिशा दी है। 8 साल की उम्र में फिल्म 'यादों की बारात' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कैमरे के सामने आने वाले आमिर ने आगे चलकर 'लगान', 'गजनी', '3 इडियट्स' और 'दंगल' जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई। किरदार के लिए महीनों तैयारी करना, स्क्रिप्ट पर गहराई से काम करना और हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश उनकी खास पहचान बन चुकी है। इतना ही नहीं शूटिंग के दौरान आमिर घड़ी नहीं देखते हैं, मोबाइल के जमाने में लंबे समय तक पेजर यूज किया। उनका मानना था कि तकनीक से ज्यादा जरूरी काम पर ध्यान देना है। यही वजह है कि उन्हें इंडस्ट्री में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहा जाता है। आज आमिर खान 61वें जन्मदिन पर जानिए उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, जो बताते हैं कि वे सिर्फ बड़े स्टार ही नहीं बल्कि अपने काम को लेकर बेहद समर्पित कलाकार भी हैं। फिल्मों से पहले आमिर खान की जिंदगी में खेल का भी बड़ा स्थान था। स्कूल के दिनों में उन्हें टेनिस खेलने का बहुत शौक था और वे स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके हैं। खेल ने उन्हें अनुशासन और धैर्य सिखाया।

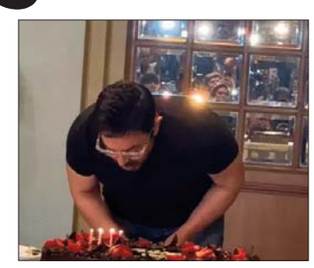

8 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने

आमिर खान का फिल्मों से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। वे सिर्फ 8 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म 'यादों की बारात' में नजर आए थे। यह फिल्म उनके चाचा नासिर हुसैन ने बनाई थी। उस समय आमिर को फिल्मों की दुनिया का ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन कैमरे के सामने आने का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहा। बाद में उन्होंने अभिनय को ही अपना करियर बनाया और बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में शामिल हो गए। उनका मानना है कि शुरुआती अनुभव ही किसी कलाकार के भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। खेल से मिली यह सीख उनके काम करने के तरीके में भी साफ नजर आती है।

66 बचपन में आमिर अक्सर अपने पिता और परिवार के साथ फिल्म के सेट पर जाया करते थे। वे घंटों बैठकर शूटिंग देखते और कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते थे। यही उनका पहला एक्टिंग स्कूल बन गया। इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा था, "मैं प्रशिक्षित अभिनेता नहीं हूं। मैंने अभिनय किसी संस्थान से नहीं सीखा, बल्कि सेट पर देखकर सीखा।" आमिर के मुताबिक हर फिल्म और हर किरदार उन्हें कुछ नया सिखाता है। यही वजह है कि वे हर रोल को बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं।

अफगानिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, पहले पाक ने काबुल पर एयरस्ट्राइक की

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों से भरे दो ड्रोन मार गिराए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन फैजाबाद इलाके के पास गिरा, जबकि दूसरा I-9 सेक्टर में गिराया गया। इससे पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार में हवाई हमले किए थे। तालिबान अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 6 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए। इस बीच पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें सामान्य रूप से जारी हैं और एयरपोर्ट बंद होने की खबरें गलत हैं। दरअसल, पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयरस्ट्राइक की थी।

पाकिस्तान ने अफगान के फ्यूल डिपो पर हमला किया था

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, पाकिस्तान ने प्राइवेट एयरलाइन 'काम एयर' के फ्यूल डिपो पर हमला किया था, जो सिविलियन विमानों और UN के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई करता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) के ठिकानों पर की गई है। हाल के महीनों में देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया।

तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने कई नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया है।

पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं के गढ़ को निशाना बनाया

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पाकिस्तानी हमले कंधार और पक्तिका प्रांतों में भी किए गए। कंधार तालिबान नेताओं का गढ़ माना जाता है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

यहूदी स्कूल के पास विस्फोट

मेयर ने कहा- यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया

एम्स्टर्डम, एजेंसी

नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में शनिवार तड़के यहूदी समुदाय से जुड़े एक स्कूल में विस्फोट होने से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके की वजह से इमारत को नुकसान पहुंचा है। डच मीडिया के हवाले से ब्रिटेन के समाचार चैनलस्काई न्यूज ने बताया कि शहर की मेयर फेम्के हल्सेमा ने इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया है।

उन्होंने कहा कि एम्स्टर्डम में यहूदी लोग लगातार बढ़ती यहूदी-विरोधी घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंच गए और स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में कर लिया गया।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) और इज़राइल (इज़राइल) हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान (ईरान) और हिजबुल्लाह (हिजबुल्ला) के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और क्षेत्र में लगातार बमबारी और सैन्य कार्रवाई जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए और स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में कर लिया गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं।

बढ़ोतरी : ₹3,000 की जगह ₹3,075 देने होंगे, 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर

1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास

नई दिल्ली, एजेंसी

अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग (FASTag) एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देशभर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। सरकार ने 15 अगस्त से इस खास एनुअल पास की शुरुआत की थी, जिसे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। अब तक 52 लाख से ज्यादा हाईवे कार यूजर्स इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। इस पास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक साल में कितनी भी बार रिचार्ज कराया जा सकता है और यह लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए काफी किफायती साबित होता है। इस पास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक साल में कई बार रिचार्ज कराया जा सकता है। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था काफी किफायती और सुविधाजनक मानी जा रही है। इसे लोगों से उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला है। अब तक करीब 52 लाख से ज्यादा हाईवे कार उपयोगकर्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं।

> सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, जब फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की गई थी, तभी इसके नोटिफिकेशन में हर साल कीमतों की समीक्षा और बदलाव का प्रावधान रखा गया था। यह बढ़ोतरी उसी सालाना रिवीजन प्रक्रिया का हिस्सा है। देश भर में हाईवे टोल की दरों में बदलाव के लिए जो फॉर्मूला तय है, उसी के आधार पर इस बार 2.5% की वृद्धि की गई है।

31 मार्च तक पुराने रेट पर खरीदने का मौका

अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और इस बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं, तो आपके पास अभी मौका है। अधिकारियों ने बताया कि जो यूजर्स 31 मार्च तक अपना पास रिचार्ज करा लेंगे या नया पास खरीदेंगे, उन्हें यह पुराने रेट यानी 3,000 रुपए में ही मिल जाएगा। 1 अप्रैल की सुबह से सिस्टम में नई दरें अपडेट कर दी जाएंगी।

200 टोल प्लाजा पर मिलती है सुविधा

यह एनुअल पास फिलहाल देश के प्रमुख 200 टोल प्लाजा पर मान्य है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बार-बार टोल टैक्स कटने की झंझट से भी मुक्ति मिलती है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में इस पास के दायरे में और भी अधिक टोल प्लाजा को शामिल करना है, ताकि कैशलेस इकोनॉमी और स्मूद ट्रैवल को बढ़ावा दिया जा सके।

एअर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें हुई महंगी

घरेलू उड़ानों पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा

नई दिल्ली, एजेंसी

एअर इंडिया के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स भी कल से महंगी हो जाएंगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 'फ्यूल सरचार्ज' लगाने की घोषणा की है एयरलाइन ने बताया कि ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग की वजह से जेट फ्यूल की कीमतें 85% तक बढ़ गई हैं। इस कारण घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकटों पर 425 से 2300 तक सरचार्ज लगाया जाएगा। एक्सट्रा फ्यूल चार्ज के साथ टिकटों की नई कीमतें 14 मार्च रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इंडिगो ने यात्रियों पर पड़ने वाले बोझ को कम रखने के लिए अलग-अलग दूरी के हिसाब से चार्ज तय किया है। कंपनी ने कहा कि जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से बढ़ी हुई लागत को वसूलने के लिए किराए में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत थी। इंडिगो ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए रखेगी और जरूरत पड़ने पर इन चार्जेस में बदलाव किया जाएगा। एअर इंडिया ने 12 मार्च से घरेलू फ्लाइट टिकटों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा रही है। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी की है। जेट फ्यूल के दाम लगातार बढ़ने से दुनियाभर की प्रमुख एयरलाइंस ने भी टिकटों के दाम बढ़ाए हैं। कई कंपनियां अपने विमानों को ग्राउंडेड करने का प्लान भी बना रही हैं। जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने के चलते दुनियाभर की एयरलाइंस ने न सिर्फ टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि अपने भविष्य के वित्तीय अनुमानों यानी फाइनेंशियल आउटलुक को भी वापस लिया है। एयरलाइंस के लिए जेट-फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। कुल ऑपरेटिंग खर्च में इसकी हिस्सेदारी 30% से 40% होती है। तेल की कीमतों में आए इस अचानक बदलाव ने एयरलाइंस के बजट को बिगाड़ दिया है। एयर न्यूजीलैंड और क्वांटास जैसी बड़ी कंपनियों ने भी साफ कर दिया है कि वे बढ़े हुए खर्च का बोझ यात्रियों पर डालेंगे।

गैस के लिए गाड़ी के रास्ते पर लेटा ग्राहक

लखनऊ में एजेंसियों पर कतारें, कालाबाजारी पर यूपी में 24 एफआईआर, 6 गिरफ्तार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर का एक ग्राहक डिलीवरी गाड़ी के रास्ते पर लेट गया। उसका कहना था कि जब तक उसे सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तक वह सड़क से नहीं उठेगा। शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। कई इलाकों में फास्ट फूड और चाय-नाश्ते की दुकानें आंशिक रूप से बंद हो गई हैं।

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन टीमों ने 1483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की, जिसमें 24 एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भारत गैस गोदाम इंचार्ज विमलेश यादव ने बताया-गैस सिलेंडर पर्याप्त संख्या में हैं। बुकिंग के बाद करीब डेढ़ सौ सिलेंडर उपभोक्ता को दिए जा चुके हैं। उतरेठीया गांव में गाड़ी लगाकर बांट रहे हैं। कैटरर्स का कहना है कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो सहालग के इस व्यस्त सीजन में शादी-समारोहों की व्यवस्थाएं संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विकासनगर में एक युवक से सिलेंडर लेने के दौरान बहस भी हो गई। एजेंसी संचालक न कहा कि कोई दिक्कत नहीं और सबको गैस मिल रही है। इसी पर वह एजेंसी संचालक से बहस करने लगा।

महिला बोली- मिट्टी के चूल्हे को दोबारा तैयार किया

निगोहां की रामवती (58) बताती हैं कि कई दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है। मजबूरी में घर में पहले इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के चूल्हे को दोबारा तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि पहले के समय में इसी तरह चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन अब लोग इसकी आदत छोड़ चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जिन घरों में अभी भी कच्ची जगह मौजूद है, वहां अस्थायी चूल्हा बनाकर खाना बनाना आसान है। लेकिन जिन घरों में पूरी तरह टाइल्स और मार्बल से किचन तैयार हो चुके हैं, वहां रहने वाले परिवारों के लिए चूल्हा जलाना संभव नहीं है। उन्हें पूरी तरह गैस सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।

सहालग में गैस संकट, कैटरर्स ने फिर जलाईं लकड़ी की भट्ठियां

मोहनलालगंज के सदगुरु कैटर्स के संचालक लल्लू ने बताया कि इन दिनों गैस सिलेंडर समय से नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार कार्यक्रम के दिन तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में मजबूरी में अस्थायी चूल्हे बनाकर लकड़ी की भट्ठियों पर ही मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना पड़ रहा है।

गोसाईंगंज के अर्जुनगंज में गैस की गाड़ी आई है। लोग लाइन में लगकर सिलेंडर ले रहे हैं।

ग्राहक बोलीं- 4 किमी लुढ़काते हुए लाए, अब सिलेंडर खाली लेकर लौट रहे

विकासनगर स्थित गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों की नाराजगी बढ़ी हुई है। एक बुजुर्ग ग्राहक ने बताया कि वह 11:30 बजे 4 किलोमीटर दूर से सिलेंडर लुढ़काते हुए लाई थीं, लेकिन अब उन्हें खाली सिलेंडर लेकर वापस जाना पड़ रहा है।

'आप' का गैस के लिए प्रदर्शन

लखनऊ। लखनऊ में AAP कार्यकर्ताओं ने गैस के लिए प्रदर्शन किया। वे स्वास्थ्य भवन चौराहे पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर-बैनर ले रखे थे। एक कार्यकर्ता ने पूरे शरीर पर बैनर पहन रखा था, जिस पर लिखा था- 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब'। पुलिस सबको हिरासत में लेने लगी। पुलिस को करीब आते देख कई कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। उसके बावजूद पुलिस ने सबको टांगकर गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद इको गार्डन भेज दिया। इससे पहले जिला अध्यक्ष इरम को पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। AAP जिला अध्यक्ष इरम ने कहा- LPG गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता के चूल्हे से आंच खींच ली गई। इसके बाद दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष शुरू हो गया है। सरकार ने लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने से रोकने के लिए सुबह सुबह मेरे घर पर ही पुलिस भेज दी। ताकि हम लोग इस जनहित के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन न कर सकें।

अब यूपीपी की वर्दी पहननी है : एक्स आर्मी मैन

लखनऊ में 54 सेंटर पर दरोगा भर्ती परीक्षा, पेपर वायरल, बोर्ड बोला- फेक है

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है। राजधानी के 54 स्कूल-कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है। कई सेंटर पर गहन चेकिंग के साथ अभ्यर्थियों के जूते उतरवा लिए गए। पायल-बिछिया भी उतरवा दी गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शिफ्ट-I का पेपर वायरल हो गया। हालांकि, भर्ती बोर्ड ने वायरल पेपर को फर्जी बताया। परीक्षा 14 और 15 मार्च को 2-2 पालियों में होगी। आज पहली पाली में करीब 22 हजार अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। अंबेडकरनगर से पेपर देने आए एक्स आर्मी मैन ने कहा- अब यूपीपी की वर्दी पहननी है। बता दें परीक्षा पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे, दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक है। परीक्षा यूपी के सभी 75 जिलों में 1090 केंद्रों पर कराई जा रही है। दूसरी पाली में परीक्षा शुरू होने वाली है। सेंटरों के बाहर अभ्यर्थी लाइन में खड़े हो गए हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। यह वीडियो विकासनगर GGIC का है। मोहम्मद हुसैन इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। वह भी पेपर देने आए। उन्होंने कहा- कमांड करने का हौसला है। अब यूपीपी की वर्दी अपने कंधे पर लानी है। बाराबंकी से आए अखिलेश कुमार ने बताया- पेपर ईजी टू मॉडरेट था। इसमें नए कानूनों के बारे में, आईटी से जुड़े भी सवाल थे। आगे की शिफ्ट वालों के लिए यही कहूंगा कि टाइम मैनेज कर लें बस। बाकी पेपर अच्छा आ रहा है।

फास्ट न्यूज

एलएसजी का इकाना स्टेडियम में लगेगा कैंप

लखनऊ। आईपीएल की तैयारियों के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) खिलाड़ियों का लखनऊ आना शुरू हो गया है। 16 मार्च से इकाना स्टेडियम में टीम का कैंप लगने लगेगा। इसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। LSG के ग्लोबल डायरेक्टर और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला खिलाड़ी टॉम मूडी और हेड कोच जस्टिन लैंगर के अलावा टीम का कोचिंग स्टाफ शनिवार को आ गया है।

कानपुर में खड़े डंपर में टकराई बस

कानपुर। कानपुर में इटावा हाईवे पर पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार टूरिस्ट बस खड़े डंपर में घुस गई। हादसे में 56 तीर्थ यात्री घायल हुए हैं। बस में 57 तीर्थ यात्री सवार थे। बस नासिक से चलकर अयोध्या होते हुए नेपाल के लिए जा रही थी। नासिक की रहने वाली 60 वर्षीय भागीरथी की और विनोद यादव उर्फ मनोज की मौत हो गई। हैलट के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष साहू ने बताया कि घायल वृद्धा को जब हैलट लाया गया था, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शव को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं, नासिक के गांव कुमारी के रहने वाले मनोज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस्पात नगर के सामने पुल के ऊपर हादसा हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पनकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कल्याणपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराया।

लखनऊ की कॉलोनी में भीषण आग

दुबग्गा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित सदरौना कांशीराम कॉलोनी के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घर के अंदर का सामान जलने लगा। इससे काले धुएं का गुबार उठने लगा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और एक घंटे में आग पर काबू पाया। कांशीराम कॉलोनी के ब्लॉक संख्या 38/1 में ऑटो चालक इरशाद अपने परिवार के साथ रहते हैं।

जानकीपुरम के शिक्षामित्र का परिवार रक्षा मंत्री से मिला, लगाई मदद की गुहार

लखनऊ के बीएलओ का 19 दिन से कोई सुराग नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और शिक्षामित्र दिलीप कुमार सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। उनका 23 फरवरी को घर से निकलने के बाद से अब तक कोई पता नहीं चल सका है। मोबाइल फोन तब से स्विच ऑफ है। दिलीप की पत्नी और परिवार के लोग 19 दिन बाद 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। जानकीपुरम क्षेत्र में रहने वाले दिलीप कुमार सिंह बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में भी कार्य कर रहे थे। 23 फरवरी को वह सुबह घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। परिवार के लोगों का कहना है कि घर से निकलने के कुछ समय बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। वह घर से बाहर जाते हुए CCTV में भी दिखे थे। उन्होंने बीकेटी SDM पर नौकरी से निकालने की धमकी देने की बात भी वॉट्सएप ग्रुप पर कही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीकेटी क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला भी दिलीप कुमार सिंह के घर पहुंचे।

दिलीप सिंह, लापता

रक्षा मंत्री बोले- खोजबीन में तेजी लाई जाए

दिलीप कुमार सिंह के लापता होने से परेशान परिजनों ने 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। परिवार ने रक्षा मंत्री से अपील की कि मामले में हस्तक्षेप कर पुलिस प्रशासन को खोजबीन तेज करने के निर्देश दिए जाएं।

आखिरी लोकेशन अनौरा कला के पास मिली

पुलिस की शुरुआती जांच में दिलीप कुमार सिंह की आखिरी लोकेशन अनौरा कला क्षेत्र के आसपास मिली है। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे आगे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। पुलिस की टीम आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है और संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि उनके बारे में कोई सुराग मिल सके।

एसआईआर कार्य के दबाव की भी सामने आई बात

परिवार और परिचितों के अनुसार दिलीप कुमार सिंह इन दिनों एसआईआर (स्पेशल इनरोलमेंट रिव्यू) कार्य में लगे हुए थे और इस काम का उन पर काफी दबाव भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हर दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

यूपी में 25 मार्च को 'नवआरंभ उत्सव', बालवाटिका में नामांकन बढ़ाने के लिए होगा विशेष अभियान

आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने पर सरकार का जोर

तमसा संकेत, संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 25 मार्च 2026 को प्रदेश के सभी को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में 'नवआरंभ उत्सव' का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का बालवाटिका में नामांकन बढ़ाना तथा अभिभावकों को प्रारंभिक शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 'नवआरंभ उत्सव' के माध्यम से 3 से 4 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को बालवाटिका से जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा की मजबूत नींव तैयार हो सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराएं, ताकि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण मिल सके। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत वर्ष 2030 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दिशा में प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'नवआरंभ उत्सव' के माध्यम से अभिभावकों को बालवाटिका की गतिविधियों, लर्निंग कॉर्नर, खेल सामग्री और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों की नियमित उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि होगी। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पात्र बच्चों की सूची अभिभावकों को उपलब्ध कराई जाएगी और क्रियाशील बालवाटिका का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे अभिभावकों को विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट, नोडल शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी और इसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल तथा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से राज्य स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि 'नवआरंभ उत्सव' के आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1592.22 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

'लखनऊ विश्वविद्यालय में दलित छात्रों को टारगेट किया जाता है'

हजरतगंज में स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, बोले- यूजीसी रेगुलेशन लागू हो

- छात्रों ने धरने पर बैठने के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। परिवर्तन चौक से विधानसभा की तरफ बढ़े तो उन्हें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास रोक लिया गया।
- परिवर्तन चौक पर छात्रों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन मीडिया को दिखाया।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय पर बिरसा आंबेडकर फुले छात्र संगठन (BAPSA) से जुड़े छात्रों ने बड़ा आरोप लगाया है। संगठन के स्टूडेंट्स ने हजरतगंज के परिवर्तन चौक पर शनिवार को प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे लिए UGC रेगुलेशन लागू किया जाए। जब तक UGC लागू नहीं होता, तब तक प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ देर धरने पर बैठने के बाद छात्रों ने वहां से विधानसभा की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने उन्हें केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के नीचे बैरिकेडिंग कर रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे मानव रावत ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है। यह सिर्फ हमारी अधिकारों की नहीं भविष्य को बचाने की लड़ाई है। न्याय मिलने तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। मांग है कि UGC गाइडलाइंस 2026 को तुरंत लागू किया जाए। Not Found Suitable (NFS) का सहारा लेकर की जा रही नियुक्तियों की पहले जांच हो। उनका कहना है कि NFS लगाने वाली समितियों की भूमिका की भी समीक्षा जरूरी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आकाश ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC, SC और ST वर्गों के साथ भेदभाव की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। छात्रों को उनके जाति के आधार पर कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सवर्ण जाति के शिक्षक सरनेम देखकर दलित छात्रों के इंटरनल में नंबर काट लेते हैं। अगर सवर्ण छात्रों के बीच दूसरे छात्रों का विवाद होता है तो शिक्षक सवर्ण छात्र का साथ देते हैं। ऐसे तमाम भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी बेहद जरूरी है।

मौत : आगरा में छोटे भाई ने पीट-पीटकर मार डाला, बचाने आई मां को धक्का दिया

मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताने पर बड़े भाई की हत्या

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आई मां को भी धक्का देकर गिरा दिया। वारदात के बाद वह भागने लगा। मां ने शोर मचाया। चीख-पुकार सुनकर गली के लोगों ने पीछाकर उसे पकड़ लिया। टीला माईथान की रहने वाली पूनम शर्मा ने बताया- वह बाग मुजफ्फर खां क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में नर्स हैं। पति की करीब 5 महीने पहले मौत हो गई थी।

मेरे दो बेटे हैं। शुक्रवार रात करीब 12 बजे बड़ा बेटा गौरव (30) और छोटा बेटा आकाश (26) घर पर थे। सभी ने साथ में खाना खाया और फिर सोने चले गए। थोड़ी देर बाद आकाश नीचे आया। उसने गौरव से मोबाइल मांगा कि जीजा को फोन करना है। गौरव ने मोबाइल दे दिया, लेकिन जब आकाश ने पासवर्ड पूछा तो उसने नहीं बताया। इस पर आकाश गुस्से में आ गया। उसने कहा- मकान का बंटवारा कर दो। बड़े भाई गौरव ने इसका विरोध किया। इस पर आकाश अपने भाई से भिड़ गया। उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे जमीन पर गिरा दिया और पेट में लात घूसे मारने लगा। लाठी-डंडे से पीटने लगा। इसके बाद एलईडी उठाकर उसके सिर पर मार दी। गौरव के सिर से खून बहने लगा।

शोर सुनकर दूसरे कमरे से मां पूनम दौड़कर आई तो आकाश ने उसे भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मां पूनम ने बताया कि जब गौरव तड़पने लगा तब आकाश ने कहा- अभी इसकी सांस चल रही है, इसे अस्पताल ले जाओ। इसके बाद मां ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल गौरव को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है।

मां ने कहा- छोटे बेटे ने उनका पूरा संसार उजाड़ दिया। वह बड़े बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उसे मार डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना शुक्रवार देर रात थाना कोतवाली के टीला माईथान इलाके की है।

गौरव के सिर में गंभीर चोट लगी। परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पृष्ठ 01 का शेष...

एलपीजी ला रहे...

सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई और फैसले भी लिए हैं। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन आवंटन में 50% कटौती की जाएगी और अगले दो महीनों में 60% सरकारी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। सरकार ने नए सरकारी वाहन खरीदने और अन्य सरकारी खरीद पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा मंत्रियों, अधिकारियों और विशेष सहायकों की विदेश यात्राओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों की अगले दो महीनों की सैलरी भी बचत के रूप में सार्वजनिक कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दरअसल, अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते पेट्रोलियम की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई गई, जिसके बाद सरकार को खर्च घटाने के कदम उठाने पड़े। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास इजराइली हवाई हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह जानकारी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमला बेरूत के पूर्वी इलाके में हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई और चार लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कई ईरानी नागरिक भारत में फंस गए थे। ईरानी अधिकारियों ने चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम कर इन नागरिकों और जहाज के गैर-जरूरी क्रू को वापस भेजा। IRIS लावन फरवरी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलान 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था और तकनीकी समस्या के कारण अब भी कोच्चि पोर्ट पर खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत लगातार तनाव कम करने और संवाद का समर्थन कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि शनिवार सुबह से ईरान की ओर से किए गए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया और सभी मिसाइल व ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक UAE की एयर डिफेंस ने 294 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1,600 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। बयान में कहा गया है कि इस दौरान हुए हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और 141 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए, जिनमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार हमले में तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि हमले में नौसैनिक माइंस के भंडारण केंद्र, मिसाइल स्टोरेज बंकर और कई अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने इसे "लार्ज-स्केल प्रिसिजन स्ट्राइक" बताया। इससे पहले एक ईरानी अधिकारी ने कहा था कि खार्ग आइलैंड से तेल निर्यात बिना किसी रुकावट के जारी है और वहां तेल कंपनियों की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं।

लॉरेंस गैंग की...

उन्होंने कहा कि मुर्मू जी को दुखी मन से अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी ने केवल मुर्मू जी का अपमान नहीं किया, बल्कि महिलाओं का अपमान किया है। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग, जब भी मतदाता शुद्धी की कोशिश करता है, टीएमसी उनपर हमला करने लगती है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही व्यवहार सेना को लेकर भी है। 2019 में बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय एजेंसिया जब इनके अपराधों की जांच करती तो ये उन्हें भी रोकते हैं। ये दिल्ली तक यही अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार चुनाव में वोटरों को धमकी, आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी देकर बंगाल में खौफ बनाकर रखना चाहती है। ये कहते हैं टीएमसी को जिसका वोट नहीं वो बंगाली नहीं, सरकारी की योजनाओं का फायदा नहीं, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के जाने का समय आ गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, बीजेपी सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। जो गुंडे आपको डराते हैं, हमारी सरकार में उनके डरभरे दिन शुरू होंगे।

पीएम मोदी की...

उन्होंने कहा कि मुर्मू जी को दुखी मन से अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी ने केवल मुर्मू जी का अपमान नहीं किया, बल्कि महिलाओं का अपमान किया है। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग, जब भी मतदाता शुद्धी की कोशिश करता है, टीएमसी उनपर हमला करने लगती है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही व्यवहार सेना को लेकर भी है। 2019 में बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय एजेंसिया जब इनके अपराधों की जांच करती तो ये उन्हें भी रोकते हैं। ये दिल्ली तक यही अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं।

भाजपा सरकार की विदेश नीति फेल : अखिलेश

कार्यक्रम के दौरान बोले- एलपीजी संकट से आम जनता और कारोबार प्रभावित

तमसा संकेत, संवाददाता

अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और एलपीजी जैसी जरूरी चीजें भी विदेश नीति से जुड़ी होती हैं। ऐसे समय में भारत को युद्ध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और शांति का संदेश देना चाहिए था। शनिवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि युद्ध की वजह से लोगों की जान जा रही है और विश्व शांति पर खतरा मंडरा रहा है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाना बनाने से लेकर रेस्टोरेंट और होटल कारोबार तक प्रभावित हो रहे हैं। उनके मुताबिक एलपीजी से जुड़ा पूरा सेक्टर संकट में है और आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि सरकार की तैयारी की कमी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता को गुमराह करती है, झूठ बोलती है और अफवाहें फैलाती है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सभी धर्म अमन और शांति का संदेश देते हैं और लोगों को मिलजुलकर रहने की सीख देते हैं।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676